>

Title: Need to repeal Article 370 of the Constitution.

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): जम्मू और कश्मीर में धारा 370 के चलते महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, विस्थापित, अल्पसंख्यकों की सामाजिक स्थिति बेहद खराब है। विकास की दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों की तुलना में जम्म् और कश्मीर बहुत पीछे है, प्रत्येक कश्मीरी के मूल अधिकार बहुत ही सीमित है, निवेश शून्य होने के कारण रोजगार के अवसर शून्य है, लोग रोजी रोटी के लिए परंपरागत कार्यों पर निर्भर है। धारा 370 हटते ही जम्मू और कश्मीर राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्र् के साथ हर क्षेत्र् में वैश्विक स्तर पर विकास कर सकता है। जम्मू और कश्मीर पर दुश्मन देश की गिद्ध दृष्टि हमेशा जमी रहती है। जिससे भारत की संप्रभुता को खतरा बना रहता है, इसलिए वहाँ पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो पाती जिसके दुष्परिणाम हमारे देश को समय-समय पर भुगतने पड़े हैं।

धारा 370 एक अस्थायी प्रबंध है, इसे अतिशीघ्र खत्म कर देश की संप्रभुता को मजबूत करने की अति आवश्यकता मौजूदा परिवेश में है।